

मुकदमों का विवरण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी सीमित

वी.

रत्नगिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस (2023 की सिविल अपील संख्या 1922)

09 नवंबर, 2023।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग-सी. ई. आर. सी. और विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण-ए. पी. टी. ई. एल. को अपीलार्थी पर शुल्क का भुगतान करने के दायित्व में न्यायसंगत ठहराया गया था।

विद्युत अधिनियम, **2003** -धारा **79**-अधिशेषित क्षमता शुल्क का भुगतान-दायित्व का निर्धारण-अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी के बीच बिजली खरीद समझौता जिसके तहत अपीलकर्ता प्रथम प्रतिवादी से बिजली खरीदेगा-प्रथम प्रतिवादी को आर. आई. एल. से गैस आपूर्ति की अनुबंधित मात्रा प्राप्त करनी थी, हालांकि आपूर्ति में गिरावट आने के बाद-कमी की भरपाई करने के लिए, प्रथम प्रतिवादी ने पुनर्चक्रित तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गेल के साथ गैस आपूर्ति समझौता-जी. एस. ए. किया और अपीलकर्ता को इसकी जानकारी दी और अपीलकर्ता से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को निर्धारित करने का अनुरोध किया- अपीलकर्ता ने निर्धारित दरों पर शक्ति निर्धारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। **79** प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा शुल्क का भुगतान न करने के लिए-सी. ई. आर. सी. ने अपीलार्थी को पी. पी. ए.-ए. पी. टी. ई. एल. के तहत शुल्क क्षमता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

आयोजित किया गया: वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो दस्तावेज़ के पक्षों के मूल उद्देश्य और इरादे के विपरीत हो-अनुबंध की साधारण शर्तों से विचलन की आवश्यकता है।

761

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

केवल तभी जब यह व्यावसायिक प्रभाव को बेहतर ढंग से पूरा करता है-अनुबंधों की व्याख्या को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार, पी. पी. ए. को समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता होती

है-प्राथमिक ईंधनों में एल. एन. जी./प्राकृतिक गैस और/या आर. एल. एन. जी. शामिल होते हैं, और तरल ईंधन का उपयोग करने के मामले में अपीलार्थी के समझौते की आवश्यकता होती है-खंड का एक खाली अध्ययन इंगित करता है कि इस तरह के समझौते की आवश्यकता खंड के पहले भाग से जुड़ी नहीं है जो आर. एल. एन. जी. को प्राथमिक ईंधन के रूप में परिकल्पना करता है-एक प्राथमिक ईंधन से दूसरे प्राथमिक ईंधन में संक्रमण से जुड़ी व्यवस्था खंड द्वारा अनुमत है, यहां तक कि अपीलार्थी के समझौते के बिना भी-तरल ईंधन से जुड़ी व्यवस्था के लिए अनिवार्य समझौते की आवश्यकता को सादे पाठ में नहीं पढ़ा जा सकता है।[पैरा 28-29,32,35-36]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वेमागिरी

पावर जेनरेशन लिमिटेड (2018) 3 एस. सी. सी. 716-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील No.1922।2013 के ए. एन. No.261 में नई दिल्ली में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 22.04.2015 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, समीर मलिक, सुश्री निकिता चौकसे, आकाश लांबा, कृष्ण कुमार, मेसर्स डी. एस. के. लीगल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सी. आर्यमन सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती स्वप्ना शेषाद्री, आनंद के. गणेशन, नितिन सलुजा, सुश्री रितु अपूर्वा, सुश्री अर्चिता कश्यप, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

763

एमएसईडीसीएल. वी. रत्नगिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई कंटेंट

4 * सी. ई. आर. सी. आदेश दिनांक 30 जुलाई 2023 और ए. पी. टी. ई. एल. निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2015।.....6* प्रस्तुतियाँ. 9 * विश्लेषण और निष्कर्ष. 13 * पी. पी. ए. की शर्तें. 13 * तथ्यात्मक संदर्भ और अनुबंध के लिए पक्षों का इरादा 17 *1. यह अपील नई दिल्ली में बिजली 1 के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से उत्पन्न होती है। ए. पी. टी. ई. एल. ने 30 जुलाई 2013 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2 के आदेश के खिलाफ एक अपील को खारिज कर दिया। 3 2. प्रथम प्रतिवादी, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड 4 नामक एक बिजली पारेषण कंपनी, ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 79 के तहत अपीलकर्ता, महाराष्ट्र राज्य

बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड 5 के खिलाफ एक याचिका का नेतृत्व किया, जिसमें घरेलू गैस की अनुपलब्धता से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करने की मांग की गई थी; प्रथम प्रतिवादी को वैकल्पिक ईंधन के लिए अनुबंध करने की अनुमति देने के लिए लाभार्थियों के आरक्षण, मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक 6 का संशोधन और लाभार्थी सहायकों को प्रथम प्रतिवादी के कारण शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. सी. ई. आर. सी. ने 30 जुलाई 2013 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी को प्रथम प्रत्यर्थी को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। सीईआरसी के फैसले को बरकरार रखा गया था

* एड नोट: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।¹ “एपीटीईएल”।

2 “सीईआरसी”।

3 2013 की अपील सं. 261 4 “आर. जी. पी. पी. एल”./प्रथम प्रतिवादी।⁵ “एम. एस. ई. डी. सी. एल./अपीलार्थी।⁶ “एनएपीएफ”।

764

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

विवादित आदेश द्वारा ए. पी. टी. ई. एल. ए. पी. टी. ई. एल. आदेश के खिलाफ दीवानी अपील का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 13 मई 2015 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी को आवश्यकता पड़ने पर अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

“इस स्तर पर इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील में उठाया गया प्रश्न अपीलार्थी के खिलाफ वसूली के लिए किसी भी दंडात्मक कदम के अभाव में अकादमिक प्रतीत होता है। इसलिए हम इस स्तर पर इस अपील पर विचार करने से इनकार करते हैं। तथापि, हम अपीलार्थी को इतनी आवश्यक होने की स्थिति में एक बार फिर इस न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता देते हैं।”

4. नतीजतन, अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के बीच शुल्क के प्रति दायित्व के संबंध में पत्राचार हुआ। अपीलार्थी ने बिजली खरीद समझौते 7 के तहत किसी भी दायित्व को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह आर. एल. एन. जी. के आधार पर प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी की सहमति के बिना क्षमता घोषणा किए जाने के बाद से शुल्क से मुक्त है। प्रथम प्रतिवादी ने 22 मई 2013 के ए. पी. टी. ई. एल. आदेश के अनुसार 1826 करोड़ रुपये की राशि के साथ ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष एक निष्पादन याचिका का नेतृत्व किया। 25 नवंबर 2022 के एक आदेश द्वारा निष्पादन याचिका पर नोटिस जारी किया गया था।

5. इस प्रकार, बाद की घटनाओं और इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आलोक में, वर्तमान अपील का नेतृत्व किया गया है।

6. आर. जी. पी. पी. एल. एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 8, एम. एस. ई. बी. होल्डिंग कंपनी, आई. सी. आई. सी. आई., आई. डी. बी. आई., एस. बी. आई. और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। इसे दाभोल पावर कंपनी लिमिटेड की संपत्तियों को लेने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका संचालन बंद करना पड़ा था। प्रथम उत्तरदाता एक पारेषण कंपनी है जो रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक गैस आधारित उत्पादन केंद्र का मालिक है। 95% इसकी क्षमता का एक हिस्सा विद्युत मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य को आवंटित किया गया है और शेष गोवा राज्य और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य को आवंटित हिस्से की आपूर्ति की जाती है।

7 "पी. पी. ए. "8 "गेल "

765

एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम रत्नागिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अपीलार्थी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी एम. एस. ई. डी. सी. एल. को। अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी ने 10 अप्रैल 2007 को 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद समझौता किया जिसके तहत अपीलार्थी प्रथम प्रत्यर्थी से बिजली खरीदेगा। उत्पादन केंद्र के तीन ब्लॉकों के लिए शुल्क का निर्धारण सी. ई. आर. सी. द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2004 के अनुसार उत्पादन केंद्र की पूंजी लागत और संयंत्र क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 7. प्रथम उत्तरदाता को आर. आई. एल. से गैस आपूर्ति की अनुबंधित मात्रा प्राप्त करनी थी। प्रथम प्रतिवादी की ओर से कहा गया है कि सितंबर 2011 तक आपूर्ति तदनुसार प्राप्त हुई थी, जिसके बाद, गैस आपूर्ति में क्रमिक गिरावट आई थी। इस कमी के लिए कम पैदावार देने वाले केजी-डी6 गैस क्षेत्र को जिम्मेदार ठहराया गया था। कम आपूर्ति का मुद्दा केंद्र सरकार के साथ उठाया गया था और 24 दिसंबर 2012 को आयोजित मंत्री समूह की बैठक में इसके समक्ष रखा गया था।

8. सितंबर 2011 से घरेलू गैस की आपूर्ति में लगातार गिरावट के कारण और आई. डी. 1 के दौरान बिजली उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए, प्रथम प्रतिवादी ने टेक-एंड-पे-कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर स्पोट कार्गो के तहत पुनर्नवीनीकरण तरल प्राकृतिक गैस 10 की आपूर्ति के लिए गेल के साथ गैस आपूर्ति समझौता/गैस परिवहन समझौता 9 किया। प्रथम प्रत्यर्थी ने 16 दिसंबर 2011 के एक पत्र द्वारा अपीलार्थी को यह जानकारी दी। इस पत्र में, प्रथम प्रतिवादी ने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी के कारण, प्रथम प्रतिवादी शुल्क आदेश में निर्धारित लक्ष्य उपलब्धता को प्राप्त करने में असमर्थ था। प्रथम उत्तरदाता के अनुसार, यह, बदले में, पूर्ण रूप से लागत वसूली करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर रहा था और परियोजना की व्यवहार्यता में बाधा डाल रहा था। अपीलार्थी से अनुरोध किया गया था कि वह प्रथम प्रतिवादी द्वारा की गई क्षमता घोषणाओं के आधार पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को निर्धारित करे।

9. अपीलार्थी ने उपरोक्त पत्र में निर्धारित दरों पर शक्ति निर्धारित करने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी ने कहा कि पी. पी. ए. के खंड 5.9 के अनुसार, प्रथम प्रतिवादी गैल के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. में प्रवेश करने से पहले अपीलार्थी की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा। इस प्रकार, आर. एल. एन. जी. पर क्षमता की घोषणा को एकतरफा और मनमाना और उल्लंघन बताया गया था।

9 “जीएसए ”/“ जीटीए ”।10 “आरएलएनजी ”

766

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

पी. पी. ए. के खंड 5.9 की शर्तें जो अपीलार्थी से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करती हैं। इसलिए, अपीलार्थी ने कहा कि वह पी. पी. ए. के अनुसार क्षमता शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त है। 17 दिसंबर 2011 से 1 मार्च 2012 तक अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी के बीच पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।

10. शुल्क का भुगतान न करने के उपरोक्त मुद्दे को हल करने के लिए, प्रथम प्रत्यर्थी ने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत एक याचिका का नेतृत्व किया, जिसमें घरेलू गैस की कमी के मुद्दे का समाधान करने की मांग की गई, ताकि लाभार्थी निकायों को ईंधन के लिए वैकल्पिक संविदात्मक व्यवस्था यानी आर. एल. एन. जी. में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके। याचिका में एन. ए. पी. ए. एफ. के संशोधन और लाभार्थियों को बकाया शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

सी. ई. आर. सी. ओ. आर. डी. ई. आर. डी. ई. डी. **30** जे. यू. एल. वाई. **2023** ए. एन. डी. ए. पी. टी. ई. एल. जजमेंट और **22** अप्रैल **2015** का अंतिम आदेश।

11. सी. ई. आर. सी. ने उपरोक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को पी. पी. ए. के तहत वास्तविक क्षमता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसने अभिनिर्धारित किया कि (i) पी. पी. ए. का खंड 4.3 'प्राथमिक ईंधन' के रूप में एल. एन. जी./प्राकृतिक गैस या आर. एल. एन. जी. के उपयोग की अनुमति देता है; (ii) प्रथम प्रतिवादी को भी तरल गैस का उपयोग करने की अनुमति है, भले ही अपीलकर्ता की सहमति से; (iii) पी. पी. ए. की शर्तें प्रथम प्रतिवादी को आर. एल. एन. जी. के आधार पर क्षमता घोषित करने से रोक नहीं देती हैं; (iv) लाभार्थी अधिकारियों के पास प्राकृतिक गैस, आर. एल. एन. जी. या तरल ईंधन पर क्षमता भेजने या भेजने से इनकार करने का विकल्प होता है; (v) यदि वे प्रेषण से इनकार करने का विकल्प चुनते हैं, तो वे पारेषण कंपनी का हवाला देते हुए शुल्क का भुगतान करने के दायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।

767

एमएसईडीसीएल. वी.रत्नगिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]12. ए. पी. टी. ई. एल. ने निम्नलिखित शर्तों में उपरोक्त आदेश को बरकरार रखा:

ए। वितरण लाइसेंसधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब बिजली उत्पादन कंपनी तरल गैस के आधार पर व्यवस्था करती है। वर्तमान मामले में, केवल एक प्राथमिक ईंधन से दूसरे प्राथमिक ईंधन यानी प्राकृतिक गैस से आर. एल. एन. जी. में परिवर्तन किया जा रहा है। पी. पी. ए. के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार ये दोनों "आर. जी. पी. पी. एल. के लिए प्राथमिक ईंधन" हैं। यह परिवर्तन, प्राथमिक ईंधन स्रोतों से तरल गैस में परिवर्तन के विपरीत, वितरण कंपनी की सहमति की आवश्यकता नहीं है; बी। पी. पी. ए. ने बिजली उत्पादन कंपनी को गेल के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. में प्रवेश करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इस संयंत्र की स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण प्रभाव के बाद की गई थी। प्रथम उत्तरदाता के पास घरेलू गैस की कमी को दूर करने के लिए गेल के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अपीलार्थी ने जी. एस. ए./जी. टी. ए. के तहत आपूर्ति की जाने वाली आर. एल. एन. जी. के आधार पर घोषित उपलब्धता के लिए शक्ति निर्धारित करने से इनकार कर दिया था।

ग. प्रथम प्रत्यर्थी ने बिजली की आवश्यक उपलब्धता की घोषणा की है जब अपीलार्थी ने घोषित उपलब्धता पर बिजली की मात्रा निर्धारित नहीं करने का विकल्प चुना है। जब तक प्रथम प्रत्यर्थी के पास घोषित उपलब्ध क्षमता है और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दी गई क्षमता निर्धारित की है, अपीलार्थी प्रथम क्षमता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; और

घ. प्रथम उत्तरदाता ने उत्पादन केंद्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव में निवेश किया है। वार्षिक शुल्क का निर्धारण 2009 के शुल्क विनियमों से उपजी विशिष्ट सी शुल्क आवश्यकताओं के संदर्भ में किया जाता है। स्टेशन में निवेश की गई पूंजी लागत की सेवा वार्षिक शुल्क के माध्यम से की जानी चाहिए।

इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. ने निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता आर. एल. एन. जी. से बिजली के लिए भुगतान नहीं करना चाहता है, तो उसे पहले प्रतिवादी को मुआवजा देना होगा, क्योंकि वह पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5 के तहत क्षमता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के दायित्व के उत्पन्न होने के लिए, अनुच्छेद 5.9 में परिकल्पित किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।

768

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

13. ए. पी. टी. ई. एल. ने इस प्रकार अभিনিर्धारित किया कि अपीलार्थी को इस तथ्य के बावजूद क्षमता शुल्क का भुगतान करने का आदेश दिया गया है कि उन्होंने गेल के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. के लिए सहमति नहीं दी है। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई।

14. ए. पी. टी. ई. एल. के फैसले के खिलाफ दीवानी अपील को शुरू में इस न्यायालय द्वारा निपटाया गया था। चूँकि अपीलार्थी को वसूली के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए अपील को खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी को आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई।

15. उपरोक्त स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील हमारे सामने है। 16. नोटिस जारी होने के बाद, प्रथम प्रतिवादी पेश हुआ और उसने एक जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया।

17. हमने अपीलार्थियों और उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील को सुना है।

प्रस्तुतियाँ

18. अपीलार्थी ने ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया:

क. सी. ई. आर. सी. ने पी. पी. ए. के खंड 4.3 और खंड 5.9 को दो अलग-अलग भागों में रखा है। पी. पी. ए. के अनुसार (खंड 4.3 और 5.9 को संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है), प्रथम प्रतिवादी गेल के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. में प्रवेश करने से पहले अपीलार्थी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य था। इस आवश्यकता को विफल करते हुए, प्रथम प्रतिवादी ने अपीलार्थी को घोषित क्षमता के लिए भुगतान करने के दायित्व से इस हद तक मुक्त कर दिया है कि ऐसी घोषित क्षमता आर. एल. एन. जी. के लिए जिम्मेदार है, जो हालांकि ईंधन का एक प्राथमिक स्रोत है, लेकिन अपीलार्थी की पूर्व सहमति के बाद ही प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जा सकता था।

बी। खंड 5.9 में पूर्व अनुमोदन खंड की नियुक्ति से पता चलता है कि यह खंड 5.2 क्षमता शुल्क के साथ-साथ खंड 5.3 ऊर्जा शुल्क पर भी लागू होता है। विवादित निर्णय दो उपखंडों और दो प्रकार के शुल्कों के बीच एक कृत्रिम अंतर करते हैं और गलत तरीके से खंड 5.9 में अनुमोदन आवश्यकता के लिए केवल खंड 5.3 (ऊर्जा शुल्क) और खंड 5.2 (क्षमता शुल्क) को विषय नहीं बनाते हैं।

ग. खंड 5.9 इस प्रकार है:

769

एमएसईडीसीएल. वी. रत्नगिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] "जीएसए/जी. एस. टी. की वाणिज्यिक प्रभाव वाली शर्तों (उदाहरण के लिए, संयंत्र की उपलब्धता, अनुबंधित मात्रा, मूल्य घटकों, लेने या भुगतान के प्रावधान, जुर्माना और नुकसान, आदि) पर पूरक समझौते के रूप में एमएसईडीसीएल के साथ अलग से हस्ताक्षर किए जाएंगे। गैस/एल. एन. जी. के लिए आवश्यक कुल राशि की खरीद गेल के माध्यम से अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से और भारत सरकार के निर्देशों के तहत दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से की जाती है, जिसका विवरण नियत समय में प्रस्तुत किया जाएगा। आर. जी. पी. पी. एल. को जी. एस. ए./जी. टी. ए. अनुबंध में प्रवेश करने से पहले अनुबंध की शर्तों और मूल्य पर एम. एस. ई. डी. सी. एल. की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।"

वाक्यांश "वाणिज्यिक निहितार्थ" वर्तमान जी. एस. ए./जी. टी. ए. पर सहमति की आवश्यकता को लागू करता है। "संयंत्र की उपलब्धता" का वाणिज्यिक निहितार्थ शुद्ध क्षमता के प्रतिशत के रूप में दैनिक घोषित क्षमता का औसत है। इस प्रकार, संयंत्र की क्षमता आर. एल. एन. जी. को अपनाने के निर्णय से प्रभावित होती है जो घोषित क्षमता की मात्रा को प्रभावित करती है। इस प्रकार, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा आर. एल. एन. जी. के उपयोग के स्वचालित रूप से "वाणिज्यिक निहितार्थ" हैं और इस प्रकार, खंड 5.9 में पूर्व अनुमोदन आवश्यकता लागू की गई थी; घ. खंड 5.9, वाणिज्यिक निहितार्थ, संयंत्र की उपलब्धता, घोषित क्षमता और खंड 4.3 में दिए गए ईंधन के चयन के संदर्भ में क्षमता की घोषणा के बीच एक "जैविक परस्पर संबंध" है। इसलिए, खंड 4.3 और 5.9 का विभाजन, जो विवादित निर्णयों का आधार है, हैरान करने वाला है।

ई. ऊपर बताए गए कारणों से, संयंत्र की उपलब्धता कारक 70 प्रतिशत से कम होगी, और इस तरह, सी. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम 2009 के खंड 21 (1) (ए) के अनुसार क्षमता शुल्क कम किया जाएगा।

च. सी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने पक्षों के बीच अनुबंध को वस्तुतः फिर से लिखा है जो संविदात्मक व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों के तहत अस्वीकार्य है। सही अध्ययन अनुबंध की शर्तों के साथ-साथ अनुबंध के पक्षों के आचरण के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान मामले में पक्षों के आचरण से पता चलता है कि अपीलार्थी का अनुमोदन 770 था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

अपीलार्थी को शुल्क शुल्क के दायित्व को संलग्न करने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता। अतीत में, इसी तरह के जी. एस. ए. के लिए, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की पूर्व मंजूरी मांगी गई थी। इस तरह, इस पिछले आचरण से जो इरादा सामने आया है, वह यह प्रतीत होता है कि इस तरह के जी. टी. ए./जी. एस. ए. के लिए सहमति की आवश्यकता एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता थी। ऐसा न करने पर, भुगतान करने के लिए अपीलार्थी का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है; और

छ. विवादित निर्णय अपीलार्थी के ग्राहकों को प्रभावित करेंगे।

19. उपरोक्त के विपरीत, प्रथम उत्तरदाता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया:

ए। अपीलार्थी की बिजली की माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। मैसर्स एनरॉन इंटरनेशनल और मैसर्स दाभोल पावर कंपनी की विफलता के बाद, उत्पादन केंद्र को पुनर्जीवित किया गया और इसकी संपत्तियों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 22.09.2005 के एक आदेश के आधार पर प्रथम प्रतिवादी आर. जी. पी. पी. एल. को हस्तांतरित कर दिया गया। एनटीपीसी लिमिटेड और गेल प्रत्येक के स्वामित्व में 23.5% शेयर थे जबकि अधिग्रहण के समय अपीलार्थी के पास प्रथम प्रतिवादी में 13.51% शेयर थे; और

बी। आर. एल. एन. जी. का उपयोग करके क्षमता घोषणा के साथ-साथ ऐसी घोषित क्षमता के आधार पर मांग क्षमता शुल्क पी. पी. ए. के खंड 4.3 और 5.2 के अनुसार हैं। पी. पी. ए. में पी. पी. ए. की समाप्ति के लिए कोई खंड नहीं था, और इस प्रकार यह वाणिज्यिक संचालन तिथि से 25 वर्षों के लिए वैध था।¹¹ इस प्रकार, अपीलार्थी समग्र रूप से पी. पी. ए. से और विशेष रूप से खंड 6 द्वारा बाध्य है। और 6.7 जो यह निर्धारित करता है कि भले ही कोई विवाद लंबित हो, अपीलार्थी ऐसी विचाराधीनता के दौरान शुल्क का 95 प्रतिशत भुगतान करने के लिए बाध्य है, जो अपीलार्थी करने में विफल रहा है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

20. विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या सी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. को शुल्क का भुगतान करने के लिए उचित ठहराया गया था।

11 “सीओडी”।

771

एमएसईडीसीएल. वी.रत्नगिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अपीलार्थी। विवाद मुख्य रूप से पी. पी. ए. की शर्तों पर निर्भर करता है। इसके बाद बताए गए कारणों के लिए, हम इस मुद्दे का उत्तर प्रत्यावेदन में देते हैं।

पीपीए की शर्तें

21. “घोषित क्षमता का अर्थ है गैस और तरल ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन द्वारा दिन की किसी भी अवधि या पूरे दिन के संबंध में घोषित मेगावाट में पूर्व-बस बिजली देने की स्टेशन की क्षमता।¹²

22. स्टेशन को संबंधित बिजली ब्लॉकों/स्टेशनों के सीओडी के बाद अपनी क्षमता का 95 प्रतिशत एमएसईडीसीएल को आवंटित करना है। एम. एस. ई. डी. सी. एल. खंड 5 में उल्लिखित पूर्ण क्षमता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और संबंधित वृद्धिशील शक्ति का हकदार होगा।¹³

23. खंड 4.3 में निम्नलिखित कहा गया है: 4.3 घोषित क्षमता

आर. जी. पी. पी. एल. के लिए प्राथमिक ईंधन एल. एन. जी./प्राकृतिक गैस और/या आर. एल. एन. जी है। आम तौर पर स्टेशन की क्षमता तीनों बिजली ब्लॉकों के लिए गैस और/या आर. एल. एन. जी. पर घोषित की जाएगी। हालाँकि, यदि एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा सहमति हो जाती है, तो आर. जी. पी. पी. एल. एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा आवश्यक मात्रा के लिए तरल ईंधन की व्यवस्था करेगी। ऐसे मामले में तरल ईंधन की क्षमता को भी उपलब्धता, घोषित क्षमता और पी. एल. एफ. गणना के उद्देश्य से तब तक ध्यान में रखा जाएगा जब तक कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा सहमत/अधिग्रहित तरल ईंधन (स्टॉक) स्थल पर उपलब्ध नहीं हो जाता।”

24. पी. पी. ए. का खंड 5 शुल्क से संबंधित है और कहता है कि स्टेशन के शुल्क का निर्धारण पूर्ववर्ती दाभोल बिजली परियोजना के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार और जी. ओ. एम. और आई. एफ. आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मॉडल के आधार पर किया जाएगा और स्टेशन की तुलना अन्य बिजली स्टेशनों के साथ नहीं की जा सकती है क्योंकि वित्तीय और तकनीकी मानकों को एक व्यवहार्य और स्वीकार्य शुल्क पर पहुंचने के लिए पुनर्गठित किया गया है।

25. पी. पी. ए. में दो भागों में शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान है: क्षमता शुल्क अर्थात् घोषित क्षमता और ऊर्जा के अनुरूप शुल्क

12 खंड 1 (बी), पी. पी. ए.। 13 खंड 2.2।1, पीपीए।

772

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

प्रभार अर्थात् वितरित वास्तविक बिजली के अनुरूप परिवर्तनीय प्रभार। संबंधित खंडों को नीचे निकाला गया है:

5.2 “क्षमता शुल्क

स्टेशन से बिजली की आपूर्ति के लिए पावर ब्लॉक का वार्षिक क्षमता शुल्क (ए. सी. सी.) रु. आर. जी. पी. पी. एल. द्वारा परिसंपत्ति अधिग्रहण के समय 96 पी./के. डब्ल्यू. एच. के क्षमता शुल्क के आधार पर प्रति वर्ष करोड़ रुपये। जी. डी. के तत्वावधान में चर्चा के अनुसार 96 पी./के. डब्ल्यू. एच. का यह क्षमता शुल्क बढ़ाकर 98.5p/KWH कर दिया गया है। 98.5p/KWH का यह क्षमता शुल्क 98.5p/KWH के स्तरबद्ध आधार पर उपरोक्त क्षमता शुल्कों के आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विचाराधीन चल रहे पुनर्गठन अभ्यास के अनुसार, 98.5p/KWH द्वारा आगे की समीक्षा और कार्यान्वयन के अधीन है, कुल वार्षिक क्षमता शुल्क प्रति वर्ष 1484.12 करोड़ रुपये है। पूर्ण क्षमता शुल्क 2150 मेगावाट (i.e. 1720MW) घोषित क्षमता के 80 प्रतिशत पर देय होगा, जो इससे कम होगी और ब्लॉक (स्टेशनों) के सी. ओ. डी. के बाद अनुपात के आधार पर वसूल की जाएगी। एमएसईडीसीएल आरजीपीपीएल से बिजली के आवंटन के अनुपात में क्षमता शुल्क का भुगतान करेगा।

5.3 ऊर्जा शुल्क:

स्टेशन से बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा शुल्क सकल ऊष्मा दर और सहायक बिजली खपत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है:

...

5.4 शुल्क गणना के उद्देश्य से मूल्य, मात्रा आदि के सभी मूल्यों को आठ दशमलव बिंदु सटीकता तक माना जाएगा।

5.5 ऊर्जा शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार स्टेशन से भेजी जाने वाली पूर्व-बस ऊर्जा के आधार पर किया जाएगा:

ऊर्जा शुल्क (रु.) = आर. ई. सी. 9 * एस. जी. गैस पर + आर. ई. सी. * एस. जी. तरल ईंधन पर

5.6 अस्थायी बिलिंग:आर. जी. पी. पी. एल. क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क के लिए गणना की गई उपरोक्त दर के आधार पर अस्थायी रूप से एम. एस. ई. डी. सी. एल. का बिलिंग करेगी और एम. एस. ई. डी. सी. एल. 773 तक उपरोक्त बिलिंग के आधार पर भुगतान करने के लिए सहमत होगी।

एमएसईडीसीएल. वी.रत्नगिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

उस समय इसे सी. ई. आर. सी. या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।सी. ई. आर. सी. या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुल्क के अंतिम अनुमोदन के बाद अनंतिम बिलिंग को समायोजित किया जाएगा।

5.9 गैस आपूर्ति समझौता (जी. एस. ए.) गैस परिवहन समझौता (जी. टी. ए.) गैस आपूर्ति समझौता वर्तमान में डेढ़ एम. एम. टी. पी. ए. आर-एल. एन. जी. के लिए सितंबर 2009 तक है, जिसे पेट्रोनेट एल. एन. जी. लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है और उनके दहेज टर्मिनल पर गेल/ऑफ-टेकर्स के माध्यम से आपूर्ति के साथ पुनः गैसीकृत किया जा रहा है।जी. एस. ए./जी. टी. ए. की वाणिज्यिक प्रभाव वाली शर्तों (उदाहरण के लिए संयंत्र की उपलब्धता, अनुबंधित मात्रा, मूल्य घटकों, लेने या भुगतान के प्रावधान, जुर्माना और नुकसान आदि) पर पूरक समझौते के रूप में एम. एस. ई. डी. सी. एल. के साथ अलग से हस्ताक्षर किए जाएंगे।गेल के माध्यम से और भारत सरकार के निर्देशों के तहत अल्पकालिक अनुबंधों/दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से कुल आवश्यक गैस/एल. एन. जी. की खरीद की परिकल्पना की गई है, जिसका विवरण नियत समय में प्रस्तुत किया जाएगा।आर. जी. पी. पी. एल. को जी. एस. ए./जी. टी. ए. अनुबंध में प्रवेश करने से पहले अनुबंध की शर्तों और मूल्य पर एम. एस. ई. डी. सी. एल. की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।”

26. पी. पी. ए. की शर्तों से उत्पन्न होने वाली स्थिति इस प्रकार तैयार की गई है:

ए। एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा देय दो प्रकार के प्रशुल्क शुल्क हैं-खंड 5 के तहत क्षमता शुल्क और खंड 5 के तहत ऊर्जा शुल्क।

बी। पूर्व के लिए, दरें निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें आर. जी. पी. पी. एल. द्वारा अधिग्रहण के समय निर्धारित किया गया है, और भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार द्वारा संशोधन के अधीन हैं।

ग. बाद वाले के लिए, दरों की गणना खंड 5.3 में निर्धारित सूत्र के माध्यम से की जानी है।

घ. एम. एस. ई. डी. सी. एल. को आर. जी. पी. पी. एल. से ऊर्जा भेजने का समय निर्धारित करना आवश्यक है और ऊर्जा शुल्क आर. जी. पी. पी. एल. से एम. एस. ई. डी. सी. एल. को भेजी जाने वाली निर्धारित ऊर्जा के अनुसार देय हैं।

ई. दो प्रकार के शुल्कों का अनंतिम बिलिंग तब तक किया जाएगा जब तक कि बिलिंग को सी. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है; और

च. भारत सरकार के निर्देशों के तहत जी. एस. ए./जी. टी. ए. के माध्यम से गेल के माध्यम से कुल गैस आवश्यकताओं की खरीद की जानी है। 774 से पहले

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

जी. एस. ए./जी. टी. ए. में प्रवेश करते हुए, आर. जी. पी. पी. एल. को अनुबंध की शर्तों और कीमत पर एम. एस. ई. डी. सी. एल. से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इस तरह के जी. एस. ए./जी. टी. ए. के 'वाणिज्यिक निहितार्थ' हैं।²⁷ प्रथम उत्तरदाता ने लगातार कहा है कि गेल के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था और आर. एल. एन. जी. पर आधारित क्षमता घोषणाएं घरेलू ईंधन की अभूतपूर्व राष्ट्रीय कमी के कारण आवश्यक थीं। लेकिन इस तरह की एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, प्रथम प्रतिवादी लक्ष्य उपलब्धता को पूरा करने में असमर्थ होता, जिसने बदले में लागत की वसूली करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया होता और परियोजना की व्यवहार्यता को खतरे में डाल दिया होता। अपीलार्थी घरेलू ईंधन की कमी पर विवाद नहीं करता है, बल्कि केवल आर. एल. एन. जी. के आधार पर क्षमता घोषित करने के "एकतरफा" निर्णय पर आपत्ति जताता है, जिसके बारे में अपीलार्थी कहता है कि इसने पी. पी. ए. के खंड 5.9 के तहत अनिवार्य अनुमोदन आवश्यकता का उल्लंघन किया है, जिससे उसे प्रत्यायोजित क्षमता शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

28. अनुबंधों की व्याख्या को नियंत्रित करने वाले तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, पी. पी. ए. को समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। खंड 4.3 के दो भाग हैं: प्रथम के अनुसार, प्राथमिक ईंधन में एल. एन. जी./प्राकृतिक गैस और/या आर. एल. एन. जी. शामिल हैं; दूसरे के अनुसार, तरल ईंधन का उपयोग करने के मामले में अपीलार्थी के समझौते की आवश्यकता होती है। खंड के एक खाली पढ़ने से संकेत मिलता है कि इस तरह के समझौते की मांग करने की आवश्यकता खंड के पहले भाग से जुड़ी नहीं है जो आर. एल. एन. जी. को प्राथमिक ईंधन के रूप में परिकल्पना करता है। एक प्राथमिक ईंधन से दूसरे प्राथमिक ईंधन में संक्रमण से जुड़ी एक व्यवस्था खंड द्वारा अनुमत है, यहां तक कि अपीलार्थी के समझौते के बिना भी।

29. तरल ईंधन से जुड़ी व्यवस्था के लिए अनिवार्य समझौते की आवश्यकता को खंड 4.3 के पूर्व भाग के सादे पाठ में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार, आर. एल. एन. जी. पर आधारित क्षमता घोषणा एकतरफा रूप से की जा सकती है, बाद की छमाही में अपीलार्थी की सहमति की आवश्यकता या पी. पी. ए. के खंड 5.9 के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के बिना।

वास्तविक पाठ और अनुबंध में भाग लेने का इरादा

30. हमें उन तथ्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए जिनके कारण प्रथम प्रतिवादी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मैसर्स एनरॉन इंटरनेशनल और मैसर्स दाभोल पावर कंपनी की महाराष्ट्र राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप की गई थी। शुल्क आवश्यकताओं को इकाई की व्यवहार्यता को संरक्षित करने की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

775

एमएसईडीसीएल. वी.रत्नगिरी गैस और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

31. आर. एल. एन. जी. को एक व्यवहार्य और संविदात्मक रूप से अनुमेय विकल्प बनाते हुए, प्रथम प्रतिवादी को घरेलू गैस की देशव्यापी कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेष रूप से, अपीलार्थी ने उन परिस्थितियों पर विवाद नहीं किया है जिनमें यह आवश्यकता उत्पन्न हुई थी।

32. वर्तमान मामले में, सी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि जी. ए. आई. एल. के साथ जी. एस. ए./जी. टी. ए. अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुज्ञेय है और अपीलार्थी की सहमति या अनुमोदन अप्रासंगिक है। खंड 5.9 और खंड 4.3 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और पूर्व की आवश्यकताओं को बाद वाले द्वारा अनुमत व्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता है।

33. खंड 5 के तहत अनिवार्य क्षमता शुल्क उस घोषित क्षमता पर निर्भर करता है जो स्टेशन अपने लाभार्थियों को देने में सक्षम है। दूसरी ओर, ऊर्जा शुल्क केवल वितरित वास्तविक ऊर्जा के बदले देय होते हैं। पूर्व के लिए अपीलार्थी का दायित्व वास्तविक वितरण अज्ञेयवादी है। यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक घोषित क्षमता पी. पी. ए. अर्थात् खंड 4.3 के संदर्भ में बनाई जाती है।

34. खंड 2.2।2 पी. पी. ए. ने यह निर्धारित किया है कि यदि एम. एस. ई. डी. सी. एल. आर. जी. पी. पी. एल. की पूरी आवंटित क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ है, या यदि एम. एस. ई. डी. सी. एल. पी. पी. ए. के अनुसार भुगतान दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, तो आर. जी. पी. पी. एल. खंड 2.2 के प्रावधानों के अधीन एम. एस. ई. डी. सी. एल. से क्षमता शुल्क की वसूली के अपने दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य पक्षों को बिजली बेचने का हकदार होगा। 2. खंड 2.2।2 पी. पी. ए. के पक्षकारों के क्षमता शुल्क को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा के दायरे से बाहर रखने के इरादे को इंगित करता है। अपीलार्थी के पढ़ने का तात्पर्य है कि इस तरह के शुल्क से बचा जा सकता है और अपीलार्थी की सहमति के अधीन किया जा सकता है। इस तरह का अध्ययन पी. पी. ए. के तहत क्षमता शुल्क को निश्चित शुल्क के रूप में मानने के पक्षों के स्पष्ट इरादे के खिलाफ जाता है।

35. एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो दस्तावेज़ के पक्षों के मूल उद्देश्य और इरादे के विपरीत हो। अनुबंध की साधारण शर्तों से विचलन केवल तभी होता है जब यह व्यावसायिक प्रभाव को बेहतर तरीके से पूरा करता है। अपीलार्थी के तर्कों को संविदात्मक

प्रावधानों के विपरीत निहित शब्दों में पढ़ना आवश्यक होगा जो अन्यथा स्पष्ट हैं। निहित शर्तों का ऐसा अध्ययन केवल संकीर्ण परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है।

यह न्यायालय संचरण निगम 776 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

आंध्र प्रदेश लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड **14**

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया: “26. एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि वह मूल रूप से पक्षों के इरादे से पूरी तरह से भिन्न हो। ऐसी स्थिति पर तभी विचार किया जा सकता है जब अनुबंध की शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए निहित अवधि को आवश्यक माना जा सके। यदि अनुबंध पक्षों के सच्चे इरादे के संबंध में अपने स्पष्ट अर्थ की व्याख्या करने में सक्षम है, तो किसी पक्ष की समझ पर निहित शब्दों को पढ़ना विवेकपूर्ण नहीं होगा, या अदालत द्वारा, व्यावसायिक प्रभाव के संबंध में।”

36. वर्तमान संदर्भ में, प्रथम प्रत्यर्थी की स्थापना की पृष्ठभूमि और प्रथम प्रत्यर्थी के नियंत्रण से परे कारणों से घरेलू गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए, सादे शब्दों से इस तरह का विचलन योग्य नहीं है और व्यावसायिक प्रभावशीलता के खिलाफ है क्योंकि इसका प्रथम प्रत्यर्थी की व्यवहार्यता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

37. ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष उपर्युक्त निष्पादन याचिका के अनुसार निष्पादन कार्यवाही जारी रखी जाए।

38. याचिका खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। 39. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन

14 (2018) 3 एस. सी. सी. 716,729 पैरा 26.